संभावना ◆ मांग और डिलीवरी सिस्टम में बेहतर संतुलन बिठा पाएं तो महंगाई के रहते विकास दर बढ़ सकती है

साथ चल सकती हैं महंगाई और विकास दर

दुनिया के उभरते बाजारों के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय संकट से पहले वैश्विक ताकतों ने इनका पक्ष लेना शुरू कर दिया था। इन अर्थव्यवस्थाओं ने बड़ी तेजी से अपना प्रभुत्व जमाया। इन्होंने न केवल उस तूफान को अपने पक्ष मोड़ने में कामयाबी पाई जिसने सही अर्थों में विकसित देशों को भी हिला कर रख दिया था, अपितु विकास के ऊंचे महामार्ग पर ये इतनी तेजी से चले कि इनकी गति ने वैश्विक विकास में भी उत्प्रेरक का काम किया।

लेखक एनसीएईआर में मैक्रो कंज्यूमर रिसर्च के डायरेक्टर हैं।

राजेश शुक्ला

दूसरी ओर शेष विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पीआईजीएस-पुर्तगाल, इटली, ग्रीस व स्पेन में वित्तीय व अन्य प्रकार की समस्याएं हावी होकर यूरो जोन को कठिन बना रही हैं, अमेरिका में रिकवरी की रफ्तार धीमी है तो चीन, भारत व ब्राजील अब वैश्विक विकास कथा के केंद्र बिंदु के रूप में जगह पा गए हैं। हालांकि इन तीनों देशों ने वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान और उसके बाद में जिस प्रकार के असाधारण कदम उठाए थे उसमें कमोडिटी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने मिल कर ऐसा गुल खिलाया कि मुद्रास्फीति में इजाफा हो गया।

यह इजाफा ऐसा था कि उससे निपटने के लिए इन देशों के सेंट्रल बैंक तैयार नहीं थे। दरअसल मुद्रास्फीति का यह स्तर सेंट्रल बैंकों के कंफर्ट जोन के स्तर से ज्यादा था। अब ऐसे हालात में सेंट्रल बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रास्ता अपनाना पड़ रहा है ताकि बढ़ती मुद्रास्फीति से आसन्न संकट का सामना किया जा सके और इस बारे में लोगों की उम्मीदें पूरी की जा सकें। पर इस कदम से एक समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि विकास दर की रफ्तार के धीमी होने की संभावना जताई जा रही है।

वैसे भारत एक उभरती हुई ताकत है और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे रह कर जीवन-यापन करने को अभिशप्त है जिसे अपनी भोजन-पानी सरीखी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और वह इसमें कामयाब भी नहीं हो पा रही है। भारत में गरीबों की हालत तो और भी ज्यादा दयनीय है। क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो तेज वृद्धि हुई है उससे पार पाना उसके लिए असंभव है, गरीब के लिए तो आसमान छूती हुई महंगाई के चलते दो जून की रोटी जुटाना ही कठिन हो गया है। यानी कि कुल मिला कर गरीबों के लिए पल-पल रोटी के लिए जी-तोड़ संघर्ष करने वाले हालात बन गए हैं।

हालांकि इस पर कई लोग यह तर्क भी देंगे कि लोगों की आय में भी तो वृद्धि हो रही है लिहाजा खपत का पैटर्न सुधर रहा है। पर आपको ध्यान देना होगा कि जैसे-जैसे आय बढ़ी है वैसे-वैसे दालों, मांस, मछली, अंडे आदि प्रोटीन समृद्ध वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी हैं। साथ ही इन चीजों की आपूर्ति भी कम हुई है लिहाजा मूल्य और भी बढ़ गए हैं ठीक इसी प्रकार की हालत हम आज देख भी रहे हैं। तो हम यह भी कहना चाहेंगे कि आप चाहे जिस तरह के तर्क दे दीजिए, जनवरी 2008 के बाद से अब तक प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन में हुई 55 फीसदी की वृद्धि को आप किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहरा पाएंगे।

यहां पर हम इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अक्षमताओं का पहाड़ खड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपूर्ति श्रृंखला का सही न होना है। हकीकत में तो इसे खाद्य-पदार्थों की महंगाई को नियंत्रण में रखने वाला होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम सब इस बात को बिना संकोच के मानेंगे कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों के विपणन व उनकी डिलीवरी की क्षमता में बेहद सुधार करने के अभी भी काफी स्कोप मौजूद हैं और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हम मुद्रास्फीति संबंधी दबावों से निपटने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

संजय डिमरी

फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां मुद्रास्फीति पर लगाम कसने का दम-खम लिए हुए हैं। मांग, क्रेडिट में बढ़ोतरी व अन्य प्रकार के मापदंडों सरीखी इन नीतियों की वजह से आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगने की संभावना भी नजर आ रही है। पर इस नियंत्रण की मात्रा कितनी होगी यह अभी साफ-साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ हालातों की वजह से कॉर्पोरेट निवेश में गिरावट आ जाएगी व वृद्धि की रफ्तार में भी कमी आ सकती है। अब तक आरबीआई का यह मानना रहा है कि वृद्धि के कुछ प्रतिशत अंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में बलिदान किए जा सकते हैं। हालांकि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की ऊंचाई के प्रमुख कारकों-खाद्य महंगाई व तेल की कीमतों पर लगाम लगाने में बेअसर साबित हुई है क्योंकि ये वैश्विक कारकों द्वारा प्रेरित होते हैं।

यहां पर सवाल यह है कि क्या वृद्धि को बनाए रखते हुए एक ही समय में मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा सकता है? मेरे विचार से हां, बशर्ते आप अत्यंत सोच-समझ कर कदम उठाएं मांग व डिलीवरी सिस्टम को सावधानी पूर्वक हैंडिल करना होगा, बस। इससे कई विसंगतियों पर लगाम लगाई जा सकेगी।